राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 94

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

फुटबॉल विश्व कप क्वालीफायर में भारत की दीवार बने गुरप्रीत सिंह संधू
>> 14

सरोकार

वैक्सीन के जरिये मलेरिया पर लगेगा अंकुश

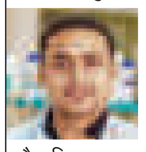

लखनऊ : भारतीय वैज्ञानिक मलेरिया का मर्म पकड़ चुके हैं। अब वैक्सीन के जरिये वे इस रोग से दो-दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ) के वैज्ञानिक इस प्रयास में जुट गए हैं। वैक्सीन निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

'बांसुरी थेरेपी' से किया जा रहा गायों का इलाज

जम्मू : पर्वतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के अंबफला (जम्मू) स्थित गोशाला में बांसुरी थेरेपी से गायों का इलाज किया जा रहा है। इससे न केवल उनका स्वभाव बदला है, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है। (पेज-10)

ओम व गाय का नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है करंट : मोदी

आशीष भटनागर, मथुरा

- प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी सोच रखने वालों ने ही देश को बर्बाद कर दिया
- कृष्ण की भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में राधे-राधे बोलकर शुरू किया संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उन आलोचकों पर तीखा प्रहार किया जो कहते हैं कि ओम और गाय शब्द का उल्लेख भारत को सदियों पीछे ले जाता है। उन्होंने कहा कि ओम शब्द सुनकर कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं तो कुछ लोगों के कानों में गाय शब्द पड़ते ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। दोनों शब्द सुनकर उनको करंट लग जाता है। ऐसी सोच रखने वालों के ज्ञान ने ही देश को बर्बाद कर रखा है। पीएम का निशाना उन लोगों पर था जो योग का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ओम का उच्चारण किया जाता है। वह बुधवार को मथुरा स्थित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी विवि में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (राष्ट्रीय पशु निरोग अभियान) के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। कृष्ण की जन्मभूमि पर उन्होंने अपना संबोधन राधे-राधे बोलकर शुरू किया। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सरकार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

टीकाकरण अभियान लांच

पीएम ने राष्ट्रीय पशु निरोग अभियान के तहत मुंह एवं खुरपका और ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान लांच किया। इसके तहत देशभर में 51 करोड़ गाय-भैंसों को टीके लगाए जाएंगे। योजना पर 15343 करोड़ खर्च होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कृष्ण नगरी मथुरा में स्थित वेटेरिनरी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पशु निरोग अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गोमाता को गेहूं-गुड़ भी खिलाया। जागरण

इनका किया शिलान्यास

- 13 करोड़ से आगरा व मुरादाबाद में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआइडीएफ) से बने पॉलीक्लीनिक।
- 117 करोड़ से बनाए 165 पशु चिकित्सालय।
- हापुड़ में 31 करोड़ रुपये की लागत से बना वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र।
- पशुओं के इलाज हेतु किसान हेल्पलाइन संजीवनी को सभी जिलों में लागू किया जाना।

पाक को आगे भी सबक सिखाएंगे

मोदी ने कहा, 11 सितंबर को ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश दिया और 11 सितंबर को ही अमेरिका में आतंकियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आतंकवाद की जड़ें पड़ोसी देश में सींची जा रही हैं। आतंकवाद के पोषकों को हमने पहले भी सबक सिखाया है और आगे भी सबक सिखाते रहेंगे।

प्लास्टिक का उपयोग बंद करें

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा, प्लास्टिक कचरा समस्या बनता जा रहा है। संकल्प लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देंगे। खरीदारी करने थैला लेकर जाएंगे। कूड़े से पॉलीथिन छांटने वाली महिलाओं से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, दो अक्टूबर तक एकत्रित कचरा प्रशासन रिसाइकिल करेगा, जो बचेगा उसे सीमेंट की फैक्ट्री या सड़क निर्माण के काम में ले लिया जाएगा। दो अक्टूबर तक घर व कार्यक्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त कर दें। बापू की जयंती पर यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उबर के खिलाफ जांच को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

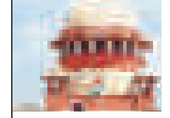

नई दिल्ली, प्रेट्र : सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) से कहा है कि वह उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छह महीनों के भीतर जांच पूरी करे। रेडिया टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर पर आक्रामक प्राइसिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एक अपीलीय प्राधिकरण ने मेरू कैब्स के इस आरोप की जांच का आदेश वर्ष 2016 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक को दिया था। उबर ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीसीआइ के महानिदेशक को तीन सितंबर से अगले छह महीनों के भीतर मामले की जांच पूरी करने को कहा है। ज्ञात हो, जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सीसीआइ को यथास्थिति का आदेश दिया था।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

मप्र में कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजपा का घंटानाद

भोपाल : मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने पूरे राज्य में घंटानाद आंदोलन कर विपक्ष के तेवर में दिखाए। विधानसभा चुनाव 2018 में पराजित होने के नौ महीने बाद भाजपा कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे और गिरफ्तारियां भी दीं।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

बच्ची को गोली मारने वाला लश्कर आतंकी मुठभेड़ में ढेर

श्रीनगर : राज्य में पाबंदियों में ढील के बाद दुकानें खोलने वालों को निशाना बना रहे लश्कर आतंकी आसिफ मकबूल को पुलिस ने सोपोर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसने ही बीते दिनों ढाई साल की बच्ची समेत चार को गोली मारी थी। मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

ब्रिटेन ने बदला वीजा नियम भारतीय छात्रों को होगा लाभ

लंदन : ब्रिटेन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले साल से विदेश से आने वाले छात्रों को पोस्ट-स्टडी वीजा दिया जाएगा। इसके तहत विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन में दो साल तक रहकर नौकरी कर सकेंगे या काम तलाश सकेंगे। नए नियम से भारतीय छात्रों को लाभ होने की संभावना जताई जा रही है।

स्पोर्ट्स ▸ पृष्ठ 14

मिशन स्पिन की तैयारी में जुटी दक्षिण अफ्रीकी टीम

धर्मशाला : दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजों की कमजोर कड़ी रही स्पिन गेंदबाजी से उबरने के लिए मेहनत कर रही है, ताकि 15 सितंबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले में भारत के स्पिन गेंदबाजों पर उसके बल्लेबाज फतह पा सकें। टीम के अंतरिम निदेशक इनोक क्वे ने नए खिलाड़ियों को नए रंग में रंगने का प्लान बनाया है।

संयुक्त राष्ट्र ने भी कश्मीर पर मध्यस्थता की अपील ठुकराई

पाक को झटका ▸ कहा, इस मुद्दे पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं

दोनों देश आपसी बातचीत से मसला सुलझाएं

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पाकिस्तान की अपील ठुकरा दी है। इस विश्व निकाय का कहना है कि इस मुद्दे पर उसका रुख पहले की तरह है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से इस मसले को आपसी बातचीत से हल करने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक प्रेस वार्ता में बताया कि एंटोनियो गुतेरस ने भारत और पाकिस्तान दोनों के नेताओं से बात की थी। उन्होंने पिछले महीने फ्रांस में जी-7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी बात की थी। सोमवार को गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी के अनुरोध पर उनसे कश्मीर मसले पर मुलाकात की थी। दुजारिक ने कहा, 'सभी के लिए उनका संदेश निजी और सार्वजनिक तौर पर एक ही रहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संभावित तनाव के प्रति बेहद चिंतित हैं। वह दोनों पक्षों से वार्ता के जरिये इस मसले से निपटने की अपील करते हैं।' दुजारिक से सवाल किया गया कि क्या इस माह के आखिर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान गुतेरस की योजना कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की है क्योंकि इस बैठक के लिए दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं? इस पर दुजारिक ने कहा, 'आप रुख जानते हैं... सैद्धांतिक रूप से मध्यस्थता पर हमारा रुख हमेशा से एक जैसा रहा है।' संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहते रहे हैं कि उनका कार्यालय तभी उपलब्ध होगा जब दोनों पक्ष इसका अनुरोध करें। भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष साफ कर चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मसला है और इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दुजारिक ने आगे कहा, 'और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की उच्चायुक्त कह चुकी हैं कि कश्मीर के हालात का समाधान मानवाधिकारों के पूरे सम्मान के साथ ही किया जा सकता है।'

मालूम हो कि जिनेवा में यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में भारत ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के अपने संप्रभु फैसले का बचाव किया था, जबकि पाकिस्तान ने इसे गैरकानूनी कृत्य करार देते हुए वैश्विक अधिकार निकाय द्वारा अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह का कहना था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाना भारत का संप्रभु फैसला था और वह देश के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीर मसले पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर निशाना साधते हुए उसके राज्य प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी।

यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विदेश मंत्रालय में प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने कहा था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद-370 एक अस्थायी प्रावधान था। उनका कहना था, 'झूठे विवरणों वाले पाकिस्तान के उन्मादी बयानों से हम कतई आश्चर्यचकित नहीं हैं क्योंकि उनका मकसद इस फोरम का राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण करना है। पाकिस्तान समझ चुका है कि हमारे फैसले ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है और उसके सीमापार आतंकवाद को प्रायोजित करने में बाधा उत्पन्न कर दी है।'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रेस वार्ता में कश्मीर पर मध्यस्थता की अपील ठुकराए जाने की जानकारी दी। रायटर

इमरान बोले, मुजफ्फराबाद में कल करूंगा बड़ा जलसा

इस्लामाबाद : कश्मीरियों के प्रति घंटेभर के लिए एकजुटता प्रदर्शन (सोलिडॉरिटी ऑवर) के फुस्स पटाखा साबित होने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को बड़ा जलसा करने की घोषणा की है। इमरान ने बुधवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है (पेज-13)

मोटर अधिनियम मामले में राजनीति की सेंध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा कर रहे आनाकानी
- पंजाब, मप्र, बंगाल ने लागू करने से किया इन्कार किया, केरल जुर्माना कम करेगा

यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त पेनाल्टी की व्यवस्था ने राज्य सरकारों के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है तो केंद्र के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। यही कारण है कि कांग्रेस शासित ही नहीं भाजपा शासित राज्यों ने भी इसमें जल्द से जल्द बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। अब केंद्र से भी लचीले रुख का संकेत दिया जाने लगा है और यह बताया जाने लगा है कि राज्य अपने स्तर पर कुछ बदलाव कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश और पंजाब ने जहां सीधे तौर पर इसे लागू करने से मना कर दिया है और कहा कि वह अध्ययन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर कुछ जुर्माने (पेनाल्टी) को बदलने का निर्णय ले लिया। झारखंड ने दूसरे राज्यों में चल रही कवायद पर नजर रखने का आदेश दिया है। केरल सरकार ने कहा है कि उसने जुर्मानाकम करने के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुर्माने को अत्यंत कठोर बताते हुए कहा, वह संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं करेंगी। ओडिशा सरकार ने पुलिस अफसरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग परेशान नहीं हों।

जाहिर है कि कुछ माह में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अंदर कसमसाहट है और जल्द ही इस कानून में बदलाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक यह लागू नहीं है। माना जा रहा है कि वहां भी कैबिनेट के जरिये बदलाव के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा में कुछ दिनों तक तो यह लागू रहा, बाद में अनौपचारिक रूप से पुलिस को कहा गया कि बड़े चालान न काटें। महाराष्ट्र में नए नियम को स्थगित कर दिया गया है।

केंद्र की भाजपा सरकार के लिए यह असहज है क्योंकि बड़ी मशक्कत के साथ इसे संसद से पारित कराया गया था। विपक्ष की ओर से इसे स्थायी समिति में भेजने का दबाव था। बताया तो यह भी जा रहा है कि पूर्व की बैठकों में भाजपा की सभी राज्य सरकारों ने समर्थन किया था लेकिन अब जनता के रोष को देखते हुए हाथ पांव फूलने लगे हैं।

राज्यों की मजबूरी अब केंद्र सरकार को भी समझ आ रही है। यही कारण है कि अब केंद्र की ओर से बताया जा रहा है कि राज्य चाहें तो वह कुछ बदलाव ला सकते हैं। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड ने यह बदलाव लाया है, लेकिन महाराष्ट्र ने औपचारिक रूप से और हरियाणा ने अनौपचारिक रूप से इसे रोक ही दिया है। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा भी ऐसा आग्रह लेकर केंद्र सरकार के सामने पहुंची है। माना जा रहा है कि केंद्र भी देर सबेर कुछ बदलाव की सोच सकता है।

वास्तविक कब्जे और कानूनी कब्जे में अंतर : मुस्लिम पक्ष

नई दिल्ली : अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे में बुधवार को मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश कीं और कहा, कानूनी रूप से वहां हक मुस्लिम पक्ष का है। हिंदू पक्ष को साबित करना होगा कि 22-23 दिसंबर 1949 (जब अंदर मूर्तियां रखी गईं थी) के पहले उनका वहां क्या अधिकार था। (पेज-3)

चिन्मयानंद प्रकरण : पैनल ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण किया

शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा का बुधवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं, छात्रा ने एसआइटी के आइजी को पत्र देकर आरोप लगाया कि हॉस्टल के कक्ष में रखे साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई। छवि खराब करने के लिए कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं रख दी गईं। (पेज-6)

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का बयान लेने एम्स पहुंची अदालत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- बंद कमरे में हुई सुनवाई, आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर भी हुआ पेश

उन्नाव दुष्कर्म कांड से जुड़े मामले की गंभीरता और पीड़िता की हालत को देखते हुए अदालत खुद एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) पहुंची, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। एम्स में बनाई गई विशेष अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। गुरुवार को आरोपित पक्ष के वकील पीड़िता से जिरह करेंगे। ध्यान रहे इस मामले में किसी भी गवाह, पीड़िता का नाम और उसका बयान प्रकाशित करने पर भी अदालत ने पाबंदी लगा रखी है।

बुधवार को तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा एम्स के कांफ्रेंस रूम में बनाई गई अस्थायी अदालत में पहुंचे। बंद कमरे में हुई इस सुनवाई के दौरान केस से संबंधित लोगों के अलावा किसी मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी। सीबीआइ तथा पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया। वहीं आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी पेश किया गया था। देर शाम तक बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेंगर के वकील ने पीड़िता से जिरह शुरू की, जो गुरुवार तक के लिए टाल दी गई।

कोर्ट को सीबीआइ ने 5 सितंबर को बताया था कि पीड़िता की हालत स्थिर है। वह बयान दर्ज करा सकती है, लेकिन अस्पताल से बाहर जाने लायक नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट की मंजूरी पर अस्पताल में अस्थाई अदालत लगी।

आम्रपाली के होमबायर्स बकाया चुकाएं : सुप्रीम कोर्ट

- कहा-वरना परियोजनाओं को बंद करना पड़ेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रोजेक्टों के घर खरीदारों (होम बायर्स) को बकाया रकम चुकाने को कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, अगर वह अपने फ्लैटों या विला की बकाया रकम नहीं चुकाते तो धन की कमी के चलते इन परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की खंडपीठ ने बुधवार को कहा, कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर के जरिये होम बायर्स को वैध करार दिए जाने के बाद उन्हें बकाया धनराशि चुकाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। अगर बायर्स बकाया रकम चुकाने को तैयार नहीं हैं तो हमें इन प्रोजेक्टों को समेटना पड़ेगा। पीठ ने कहा, 'वह आम्रपाली ग्रुप से कम कीमत पर फ्लैट खरीदने की इजाजत नहीं देगी। खरीदार सभी बकाया रकम चुकाएं अन्यथा उनके फ्लैट के पंजीकरण को रद किया जाएगा।'

कंस्ट्रक्शन प्लान की दुहाई : इससे पहले एक खरीदार की ओर से तर्क दिया गया कि उसका फ्लैट आम्रपाली लेजर पार्क सी-कैटेगरी में आता है। बिल्डर-बायर समझौते के तहत पेमेंट प्लान तो कंस्ट्रक्शन से लिंक किया गया है। यानी बिल्डिंग पूरी होने के क्रम में ही तय राशि समय-समय पर बिल्डर को दी जाती है। जमीन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरी रकम क्यों चुकाऊं।

बकाया चुकाने को तैयार रहें : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप (घर खरीदार) रकम नहीं चुकाना चाहते तो हम आपको वापस घर लौट जाने को कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो तो बकाया रकम चुकानी होगी। आप सब बकाया रकम को जमा करने के लिए तैयार रहिए।

बकाएदारों की सूची वेबसाइटों पर होगी पेज>>7

सार्थक कदम

तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना देना मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है, यही कारण है कि इस दिशा में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं

देश के 10 और शहरों में खुलेंगी अटल अकादमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फैसला
- पांच शहरों में परीक्षण के तौर पर एक साल पहले से चल रही हैं केंद्र सरकार की ये अकादमी

तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई देने और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 10 और बड़े शहरों में अटल (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन-ट्रेनिंग एवं लर्निंग) अकादमी खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल जिन 10 शहरों में अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया है, उनमें पटना, कानपुर, देहरादून, भोपाल, चेन्नई, मुरथल, बेंगलुरु, श्रीनगर, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं।

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन (एआइसीटीई) ने पिछले साल ही देशभर में इस तरह की अकादमी खोलने का निर्णय लिया था। इसके तहत बतौर ट्रायल जयपुर, वडोदरा, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में यह अकादमी शुरू की गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को एआइसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के कार्यक्रम में इसका एलान किया। इसके साथ ही उन्होंने तकनीकी संस्थानों को स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

एआइसीटीई से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में और अटल अकादमी खोलने का यह फैसला ट्रायल के तौर पर शुरू की गईं सभी पांचों अकादमी से मिले अच्छे रुझानों के बाद लिया गया है। आने वाले दिनों में अटल अकादमी देश के सभी बड़े शहरों में स्थापित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने की यह कवायद ऐसे समय शुरू की है जब देश में खराब गुणवत्ता और खाली सीटों के चलते पिछले कुछ वर्षों में करीब 800 तकनीकी संस्थान बंद हो चुके हैं। साथ ही देश के करीब 200 और तकनीकी संस्थानों ने बंद करने की अनुमति मांगी है। संस्थानों के बंद होने के पीछे योग्य शिक्षकों की कमी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी वजह हैं। इसके चलते इनकी ज्यादातर सीटें खाली रह जाती हैं।

कैसी होंगी अटल अकादमी

एआइसीटीई के मुताबिक अटल अकादमी में शोध, नवाचार और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें उस क्षेत्र के सभी तकनीकी संस्थानों को जोड़ा जाएगा जहां इन संस्थानों के शिक्षक, छात्र सहित इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी शोधार्थी अपने सपनों को साकार कर सकेगा। अकादमी में एक वर्कशॉप भी स्थापित होगी, जिसमें आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, थ्री-डी प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग, वर्चुअल रियलिटी और आगुमेंटेड रियलिटी आदि गतिविधियां शामिल होंगी।